बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 196 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 05 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में रिश्तेदार ही निकला ब्लैकमेलर, घर की महिला की आपत्तिजनक फोटो दिखाता था, अब गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को यूपी के बुलंदशहर से अरेस्ट किया है. आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी ही रिश्तेदार महिला की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजकर उसे ब्लैकमेल किया. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया. दिल्ली के नॉर्थ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल में धारा 67A IT एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई. इसमें शिकायतकर्ता प्रियांशु मकान ने दिल्ली पुलिस को बताया कि एक जान-पहचान का व्यक्ति उनकी बहन को अश्लील फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम के जरिए भेज रहा है और उसे लगातार धमकी दे रहा है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो यह सामग्री सार्वजनिक कर देगा.

हर भारतीय ने चीन पर सरकार से जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार पर कांग्रेस की सफाई

नई दिल्ली । भारतीय सेना और चीनी कब्जे वाले बयान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा कि 2020 की गलवां घटना के बाद से हर देशभक्त भारतीय सरकार से चीन पर जवाब मांग रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी डीडीएलजे - इनकार, ध्यान भटकाना, झूठ बोलना और उचित ठहराना नीति के साथ सच्चाई को धुंधलाने और छिपाने का विकल्प चुना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 1962 के बाद से भारत को मिले सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके के लिए जिम्मेदार है।

कांग्रेस ने सरकार पर अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण शत्रुतापूर्ण चीन के साथ सामान्यीकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 15 जून 2020 को गलवां में 20 बहादुर सैनिकों के शहीद होने के बाद से हर देशभक्त भारतीय जवाब मांग रहा है। फिर भी जवाब देने के बजाय मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में डीडीएलजे - इनकार, ध्यान भटकाना, झूठ बोलना और उचित ठहराना की नीति के साथ सच्चाई को धुंधलाने और छिपाने का विकल्प चुना है। एक्स पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को हमारे सैनिकों द्वारा गलवां में देश के लिए वीरतापूर्वक अपने प्राणों की आहुति देने के केवल चार दिन बाद न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है कहकर चीन को क्लीन चिट क्यों दे दी उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना

चाहते हैं। क्या 21 अक्तूबर 2024 का वापसी समझौता हमें यथास्थिति पर वापस ले जाता है जयराम रमेश ने कहा कि क्या भारतीय गश्ती दल को देपसांग, डेमचोक और चुमार में गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने के लिए चीन की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम थे। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय गश्ती दल को गलवां, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंगत्सो में अपने गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने से बफर जोन द्वारा नहीं रोका जा रहा है, जो मुख्य रूप से भारतीय दावा रेखा के भीतर हैं। उन्होंने कहा कि क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का एक हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीनी नियंत्रण में आ गया है। इसमें देपसांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है क्या लेह के एसपी ने वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत नहीं किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 गश्ती बिंदुओं में से 26 तक पहुंच खो दी है ।

जयराम रमेश ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि चीन से आयात तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बैटरी और सौर सेल का आयात बढ़ा है और दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र चीनी आयात पर निर्भर हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सच नहीं है कि चीन के साथ व्यापार घाटा 2024-25 में रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार एक ऐसे देश के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जे-10सी लड़ाकू विमान और पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों की आपूर्ति की थी और भारतीय सैन्य अभियानों में लाइव इनपुट प्रदान किया था, जैसा कि चार जुलाई 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था रमेश ने कहा कि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार 1962 के बाद से भारत को मिले सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके के लिए जिम्मेदार है और वह अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण शत्रुतापूर्ण चीन के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है।

दिल्ली में सुबह की सैर पर निकलीं कांग्रेस सांसद से चेन छीन ले गया बदमाश

नई दिल्ली।

दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि सुबह की सैर पर निकलीं कांग्रेस सांसद की चेन छीन ली गई. ये चेन स्नेचिंग की घटना दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुई जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. जहां तमाम सरकारी ऑफिस मौजूद है और सुरक्षा बंदोबस्त भी एकदम चाक-चौबंद रहते हैं. ऐसे में कांग्रेस नेता के गले से सरेआम चेन छीनकर ले जाना दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. तमिलनाडु कांग्रेस सांसद आर. सुधा ने एनडीटीवी से कहा आज सुबह 6 बजे, तमिलनाडु भवन से 500-600 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई. मैं चिल्लाई लेकिन उसने मेरी चेन छीन ली. मैंने स्पीकर को शिकायत दी है. पुलिस को शिकायत दी है और शिकायत ले ली है. मैंने गृह मंत्रालय को शिकायत भेज दी है. कांग्रेस सांसद ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब वह अपनी साथी सांसद, डीएमके की रजती के साथ पोलिश दूतावास के पास सैर पर निकली थीं.

गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

कांग्रेस सांसद ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था की देखरेख करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा और कहा कि स्कूटर पर सवार हेलमेट पहने एक व्यक्ति ने उनकी चेन छीन ली. चेन छीनने वाले उनकी दूसरी दिशा से पास आया और मेरी सोने की चेन छीनकर भाग फरार हो गया. कांग्रेस सासंद ने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि क्योंकि वह दूसरी दिशा से धीरे-धीरे आ रहा था, इसलिए मुझे इस तरफ का कोई शक नहीं हुआ कि वह चेन स्नैचर हो सकता है.

हम मदद के लिए चिल्लाए...

कांग्रेस सांसद ने बताया कि जैसे ही उसने मेरी गर्दन से चेन खींची, मेरी गर्दन पर चोटें आई. हालांकि मैं किसी गिरने से जरूर बच गई और तब हम दोनों मदद के लिए चिल्लाए. कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पेट्रोलिंग वाली गाड़ी को बताया, लेकिन पुलिस ने उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की.

चलती डीटीसी देवी बस के ड्राइवर ने खोया नियंत्रण, कई वाहनों को मारी टक्कर, ऑटो-रिक्शा चालक की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में सुबह एक दर्दनाक घटना घटी है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गयी डीटीसी देवी बस चालक ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया जिसके बाद बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इस हादसे में एक की मौत भी हो गयी। इसी के साथ दिल्ली परिवहन निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि बस चालक को अचनाक कुछ स्वास्थ समस्या हो गयी थी। या फिर कथित तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि बस में कोई समस्या थी.. ये जब जांच का विषय है। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्या है ये डीटीसी की देवी बस सर्विस। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सोमवार सुबह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) देवी बस के कथित तौर पर कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद उसकी चपेट में आकर एक ऑटोरिक्शा चालक की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बस चालक को कथित तौर पर कोई स्वास्थ संबंधित समस्या होने के कारण उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ऑटो-रिक्शा से टकरा जाने से पहले बस ने छह-सात वाहनों को टक्कर मारी। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब नौ बजे हुई। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया था। इन देवी बसों की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रणाली के विस्तार के एक बड़े प्रयास का हिस्सा थी। वर्तमान में, शहर में 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई।

ये बसें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि साल के अंत तक 2,080 और इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएँगी। जेबीएम समूह ने 400 नई बसों में से 120 का निर्माण किया है, जो गाजीपुर डिपो से चलेंगी। इसके साथ ही, जेबीएम की अब राजधानी में 650 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। जेबीएम ऑटो के उपाध्यक्ष निशांत आर्य ने कहा, आज का लॉन्च इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे सरकार और उद्योग के बीच सहयोगात्मक नवाचार शहरी गतिशीलता को नई परिभाषा दे सकते हैं। जेबीएम में, हम सिर्फ़ इलेक्ट्रिक बसें ही नहीं बना रहे हैं-हम एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करता है।

बसों की विशेषताएँ

बसों में एक वास्तविक समय यात्री सूचना प्रणाली (रीयल-टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम) शामिल है। यह प्रणाली लाइव लोकेशन ट्रैकिंग प्रदान करती है। बस में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली (सीसीटीवी) लगाई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टॉप रिक्वेस्ट बटन उपलब्ध हैं। बसें अग्नि संसूचन और अलार्म सिस्टम से सुसज्जित हैं। सक्रिय रखरखाव के लिए वाहन स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियाँ भी मौजूद हैं। चालक क्षेत्र में एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड हैं। ये डैशबोर्ड न्यूनतम विकर्षण और अधिकतम नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ECOLIFE को चालक-केंद्रित वाहन के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

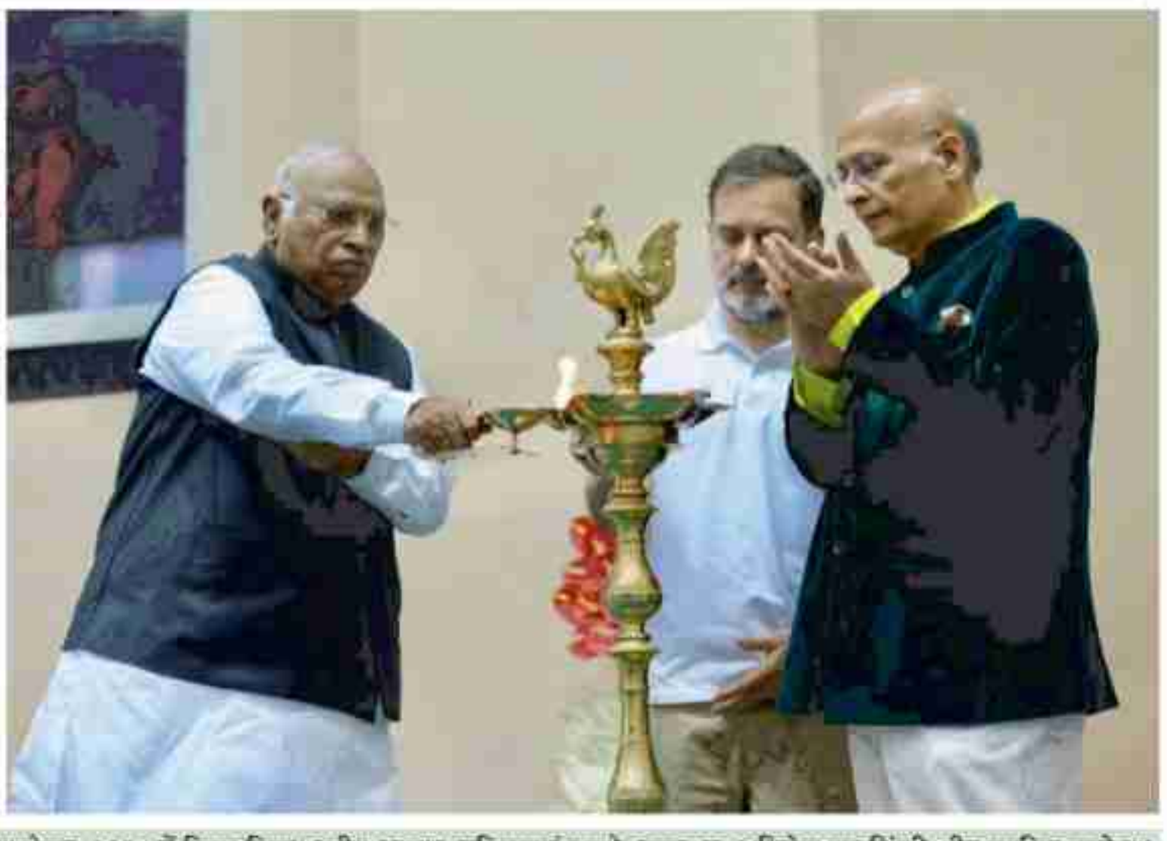

नई दिल्ली (विजय कुमार भारती)विज्ञान भवन में AICC के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक विधिक सम्मेलन, 2025 में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, व, अभिषेक मनु सिंघवी, दीप प्रज्वलित करते हुए, हमारा संविधान हर एक भारतीय के लिए सुरक्षा कवच है। कांग्रेस पार्टी हर हाल में इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। छाया- आकाश शक्य

कल्याणकारी खर्चों को पलटता पूंजीवाद

प्रभात पटनायक

विश्व युद्ध के फौरन बाद, जब पूंजीवाद के सामने गंभीर अस्तित्वगत संकट आ खड़ा हुआ था, उसने इस संकट से निपटने के लिए एक दुहरी रणनीति अपनायी थी। इस रणनीति का पहला पक्ष यह था कि ''लाल रंग का डर'' फैलाया गया, जिसका कोई औचित्य था ही नहीं। इसका मकसद घरेलू मजदूर वर्ग को आतंकित करना था, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था के लिए उससे हामी भरवायी जा सके। दूसरा पक्ष यह था कि उसे अपनी कार्यप्रणाली में समायोजन करने पड़े थे, जिनमें से चार खासतौर पर ध्यान देने वाले हैं। ये हैं औपनिवेशिक राजनीतिक निरुपनिवेशीकरण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित जनतांत्रिक शासन लाना, आम बेरोजगारी को मिटाने के लिए केंसवादी ''मांग प्रबंधन'' को स्वीकार करना और हर जगह तथा खासतौर पर पश्चिमी यूरोप में, कल्याणकारी राज्य के कदमों को अपनाना। ये बदलाव इतने महत्वपूर्ण थे कि यह छवि ही बन गयी कि ''पूंजीवाद बदल गया है'', कि यह अब वह पुराना लुटेरा पूंजीवाद नहीं रह गया है, जो पहले हुआ करता था बल्कि एक नया ''कल्याणकारी पूंजीवाद'' हो गया है। इसके बाद आए लंबे युद्धोत्तर उछाल के दौरान जब वित्तीय पूंजी ने ताकत हासिल कर ली और जब वित्तीय पूंजी वैश्विक हो गयी, जिससे राष्ट्र-राज्य की स्वायत्तता का क्षय होने का और हर जगह नव-उदारवादी निजाम थोपे जाने का रास्ता तैयार कर दिया, उक्त युद्धोत्तर कदमों को वैसे भी पलटा जा रहा था। बहरहाल, इस पलटे जाने ने अब एक अभूतपूर्व गति हासिल कर ली है। महागणीय पूंजीवाद की मदद से, फिलिस्तीनियों पर जिस तरह का खुल्लमखुल्ला नरसंहार हो रहा है, अपनी नृशंसता में अगर औपनिवेशिक दौर से ज्यादा नहीं भी है, तब कम भी नहीं है। नव-फासीवाद के उभार और पूंजीवादी तानाशाही के उभार ने, जनता को उपलब्ध जनतांत्रिक अवकाश को सिकोड़ दिया है। वैश्वीकृत वित्त के वर्चस्व के चलते, विश्व पूंजीवाद के आर्थिक संकट का अब केन्सवादी मांग प्रबंधन से उपचार नहीं किया जा सकता है। और अब मुख्यतया इसकी कोशिश और हो रही है कि हर जगह कल्याणकारी खर्चों को पलटा जाए और इससे बचने वाले संसाधनों का उपयोग, पूंजीपतियों के हक में वित्तीय हस्तांतरण करने के लिए और सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का ''बिग ब्यूटीफुल बिल'', जो अमेरिका में दोनों सदनों में पारित हो चुका है और अब कानून बन गया है, कल्याणकारी खर्चों पर बहुत भारी हमला है। कांग्रेसियोनल बजट ऑफिस के अनुसार, जो अमेरिकी सरकार से स्वतंत्र रूप से आकलन करता है, यह विधेयक अगले दस वर्षों में कुल मिलाकर 4.5 ट्रिलियन डालर (45 खरब डालर) मूल्य की कर रियायतें देने जा रहा है। और इन कर रियायतों के मुख्य लाभार्थी धनिक वर्ग के लोग होंगे। इसके अलावा, सैन्य खर्चे कुल मिलाकर 150 अरब डालर बढ़ जाने वाले हैं और ''सीमा सुरक्षा'' (यानी प्रवासियों को देश की सीमाओं में बाहर ही रखने) पर खर्चों में 129 अरब डालर की बढ़ोतरी होने जा रही है। इन सारे खर्चों की पूर्ति की जाएगी, मेडिकएड में 930 अरब डालर की कटौती से, हरित ऊर्जा में 488 अरब डालर की कटौती से और भोजन सहायता में 287 अरब डालर की कटौती से। मेडिकएड वह कार्यक्रम है, जो अमेरिकी समाज के सबसे कमजोर तबकों की मदद के लिए है, जैसे बुजुर्ग, गरीब और विकलांग। इस कार्यक्रम में कटौती करना, जो कि यह बिल करता है, समाज के सबसे लाचार तबकों पर चोट करना है। ट्रंप का ''बिग ब्यूटीफुल बिल'' बड़ी नंगई के साथ, सबसे कमजोर तबकों से लाभ छीनकर, सबसे धनी तबकों के हाथों में हस्तांतरित कर देता है। बेशक, जो कर रियायतें दी जा रही हैं, खर्चों में पीछे जिन कटौतियों का जिक्र किया गया है, उनसे भी कहीं बड़ी हैं। इसके चलते, अमेरिका में राजकोषीय घाटा अगले एक दशक में सब मिलाकर 3.4 ट्रिलियन (34 खरब) डालर बढ़ने जा रहा है। संक्षेप में यह कि अमेरिकी सरकार, खुद कर्जा भी ले रही होगी और अपने कल्याणकारी खर्चों में कटौतियां भी कर रही होगी, और यह सब सिर्फ इसलिए, ताकि अमेरिकी धनिकों के हाथों में और संपदा दे सके। इसे अर्थव्यवस्था में नयी जान डालने के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, अगर अर्थव्यवस्था में नये प्राण फूंकना ही मकसद होता, तो सरकार को कर्जा ले जाने वाली रकम सीधे खुद ही खर्च करनी चाहिए थी।

लेकिन, ऐसा करने के बजाए वह तो यह सारी क्रय शक्ति अमीरों के ही हाथों में देने जा रही है। अर्थव्यवस्था को उबारने करने के लिहाज से इसका असर बहुत ही मामूली होगा। यह तो धनिकों की संपदा में मुफ्त में इजाफा करने जैसा ही है। यहां एक सवाल उठ खड़ा होता है। वित्तीय पूंजी, राजकोषीय घाटे के बढ़ने को नापसंद करती है। जब अमीरों के हाथों में हस्तांतरणों को वित्त व्यवस्था के लिए ही राजकोषीय घाटे बढ़ाए जा रहे हों, तब भी वित्तीय पूंजी इन राजकोषीय घाटों को पसंद नहीं करती है। वास्तव में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं लिज ट्रस ने यही तो करने की कोशिश की थी। लेकिन, उनके कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था पर विरोध इतना ज्यादा था कि पाउंड स्टर्लिंग का मूल्य गिर गया और लिज ट्रस को इस्तीफा ही देना पड़ गया। इस प्रकरण में वह ब्रिटेन के पूरे इतिहास की सबसे कम अवधि की प्रधानमंत्री बन गयीं, जिनका कार्यकाल 50 दिन से ज्यादा का नहीं रह पाया। तब वित्तीय पूंजी ने डोनाल्ड ट्रंप को इसकी इजाजत कैसे दे दी कि अमीरों के लिए हस्तांतरण बढ़ाने के लिए, ज्यादा कर्ज उठा ले? बेशक, यह अब भी साफ नहीं है कि क्या ट्रंप वाकई राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी को चलाने कामयाब हो गया है यानी यह प्रश्न अब भी अपनी जगह है कि क्या वित्तीय पूंजी उसे, राजकोषीय घाटे में और कटौती करने के लिए मजबूर नहीं कर देगी और कोई जरूरी नहीं है कि वह ऐसा अमीरों की ओर हस्तांतरणों में कमी करने के जरिए करे बल्कि वित्तीय पूंजी, कल्याणकारी खर्चों में और ज्यादा कटौतियां कराने के जरिए भी तो ऐसा कर सकती है। वैसे भी ट्रंप के पास कुछ गुंजाइश है, जो इस तथ्य से जुड़ी हुई है कि आज अमेरिकी डालर की जो हैसियत है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की हैसियत से काफी भिन्न है। दुनिया के संपत्तिधारी अब भी डालर को करीब-करीब 'सोने जैसा खरा' मानते हैं और इसकी संभावना नहीं है कि ट्रंप के राजकोषीय घाटा बढ़ाने से, वे डालर को छोड़कर और किसी मुद्रा को अपना लेंगे। यह ऐसी गुंजाइश है जो लिज ट्रस को उस समय उपलब्ध नहीं थी, जब उन्होंने ब्रिटिश अमीरों के पक्ष में घाटे की वित्त व्यवस्था के बल पर हस्तांतरण करने की अपनी कुख्यात योजना को लागू करना चाहा था। कल्याणकारी खर्चों में इस समय अमेरिका में जो कटौती हो रही है, उसका जल्द ही पूरी विकसित पूंजीवादी दुनिया में ऐसी ही कटौतियों से अनुसरण किया जाएगा। 24-25 जून को हेग में हुए नाटो के शिखर सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि नाटो के सभी सदस्य देश 2035 तक सैन्य खर्चा बढ़ाकर जीडीपी का 5 फीसद कर देंगे। वर्तमान खर्चा जीडीपी के 2 फीसद के करीब है और कई देशों में तो उतना भी नहीं है। दूसरे शब्दों में नाटो के देश, खासतौर पर यूरोप के देश, एक दशक के अंदर अपने सैन्य खर्च को 2 फीसद से बढ़ाकर 5 फीसद करने की योजना बना रहे हैं। अब, नाटो के अन्य देशों की मुद्राओं की हैसियत, अमेरिकी डालर की जैसी तो है नहीं। इसलिए, ये वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी की इच्छा के खिलाफ जाकर, अपने जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके अलावा नाटो के ज्यादातर यूरोपीय सदस्य, जो कि यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, वैधानिक रूप से इस शर्त से बंधे हुए हैं कि वे अपने राजकोषीय घाटे को अपने जीडीपी के 3 फीसद से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रुख को देखते हुए भारत के साथ अमेरिकी सम्बन्ध ऐसे महीन तार पर चल पड़े हैं जिसके थोड़ा भी इधर-उधर हो जाने से भारी दुर्घटना होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत-अमेरिकी सम्बन्धों की चर्चा आपसी व्यापार के सन्दर्भ में देश के चौक-चौराहों तक होने लगी है। हाल के ताजा वर्षों के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब आम जनता द्विपक्षीय सम्बन्धों पर चल रही बहस में हिस्सा ले रही है। 2008 में पहले ऐसा हो चुका है। उस समय भारत में डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी और भारत अमेरिका से परमाणु समझौता करने जा रहा था। तब भी भारत के गांव-कस्बों में इस करार के बारे में आम जनता बहस करती हुई मिल जाती थी। यह लोकतन्त्र की ताकत थी। 2008 में इस परमाणु करार की बागडोर तत्कालीन विदेश मन्त्री भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी संभाले हुए थे। संसद से लेकर सड़क तक तब परमाणु करार के विभिन्न उपबन्धों के बारे में आम जनता भी बहस में उलझी हुई थी क्योंकि तत्कालीन विपक्षी पार्टी भाजपा इस समझौते का विरोध कर रही थी। एक मायने में यह भारतीय लोकतन्त्र के परिपक्व होने की तसदीक भी थी क्योंकि आम जनता भारत की विदेश व रक्षा नीति पर खुलकर अपने विचार रख रही थी। भाजपा के साथ-साथ वामपंथी दल भी इस समझौते का पुरजोर विरोध कर रहे थे। मगर स्व. प्रणव दा ने भारत की शर्तों पर यह समझौता इस प्रकार किया था कि भारत के परमाणु परीक्षण करने के अधिकार बरकरार रहे थे।

यह कार्य तत्कालीन सरकार में केवल प्रणव दा ही कर सकते थे क्योंकि उन्होंने भरी संसद में ऐलान कर दिया था कि यह समझौता भारत की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुखी और सुरक्षित बनायेगा। उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों ने हम पर विश्वास करके हमें सत्ता में बैठाया है अतः हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वह भारत के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए है। परमाणु करार के बारे में उनके संसद के दोनों सदनों में दिए गये भाषण संसदीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ कहे जा सकते हैं जिनसे आने वाली राजनीतिज्ञों की नस्लें सर्वदा प्रेरणा लेती रहेंगी। अतः भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर भारत की सरकार जो भी कदम उठा रही है या उठायेगी, वे राष्ट्रहित में सर्वोच्च स्थान रखने चाहिए। वर्तमान मोदी सरकार को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा और दुनिया को बता देना होगा कि भारत राष्ट्रपति ट्रम्प की उन धमकियों के आगे नहीं झुकेगा जिनसे राष्ट्र के हितों पर थोड़ी भी चोट पहुंचती हो। इस मामले में विदेशमन्त्री एस. जयशंकर को हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा और अमेरिका को बताना होगा कि भारत के विशालतम बाजार को अमेरिका अनदेखी नहीं कर सकता है।

श्री ट्रम्प भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताकर केवल अपनी कमजोरी ही जता रहे हैं क्योंकि यदि ऐसा होता तो अमेरिका भारत से यह कदापि न कहता कि वह अमेरिका से आयात किये जाने वाले सामान पर शुल्क की दरों में कमी लाये। इसके साथ ही ट्रम्प भारत से अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले सामान पर शुल्क की दरों में वृद्धि कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि अमेरिका में भारतीय माल महंगा हो जायेगा। फिलहाल भारत-अमेरिका के व्यापार में भारत का पलड़ा भारी है क्योंकि वह 46 अरब डॉलर के फायदे में है अर्थात भारत जितना अमेरिका से आयात करता है उससे कहीं ज्यादा निर्यात करता है। परन्तु ट्रम्प चाहते हैं कि भारत का यह व्यापार मुनाफा कम हो और अमेरिका का भारत को निर्यात बढ़े। ट्रम्प अमेरिकी कृषिजन्य उत्पादों से लेकर अन्य उपभोक्ता सामग्री पर भारत द्वारा लगाये गये शुल्क में गुणात्मक कमी चाहते हैं। इससे भारत में उसके उत्पाद सस्ते होंगे जिससे उनकी मांग भारतीय बाजारों में बढ़ेगी। मोदी सरकार ने हर कदम पर यह साफ कर दिया है कि वह भारत के किसानों के हितों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं होने देगी और ऐसा व्यापार समझौता करेगी जिससे दोनों देशों के हित सन्तुलित रहें। दरअसल राष्ट्रपति ट्रम्प जिस प्रकार द्विपक्षीय वाणिज्य समझौते विभिन्न देशों से करने को उतावले हो रहे हैं वह विश्व व्यापार संगठन की भावना के अनुकूल नहीं है। भारत इस संगठन का सदस्य है और उसका शुल्क ढांचा अभी तक संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही रहा है। 1990 में जब भारत इस संगठन का सदस्य बना था तो अमेरिका ने भारत पर लगे विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये थे। ये प्रतिबन्ध भारत द्वारा 1974 में पोखरन में परमाणु विस्फोट करने के बाद लगाये गये थे। भारत ने जब अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण 1991 से करना शुरू किया तो अमेरिका ने उसके इस कदम को ऐतिहासिक तक बताया। इसके बाद भारत बाजार मूलक अर्थ व्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ा। मगर भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में साफ किया कि वह किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को बन्द नहीं कर सकता क्योंकि बदलते विश्व आर्थिक परिदृश्य में यह क्षेत्र निश्चिन्तता के साथ चलना चाहिए क्योंकि भारत के साठ प्रतिशत से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनकी रोजी-रोटी यही क्षेत्र देता है। जबकि यूरोप व अमेरिका में तस्वीर दूसरी है। इस मामले में 2006 में भारत ने तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में यहां तक कह दिया कि जब तक भारत व अन्य गरीब देशों के किसानों की आर्थिक हालत यूरोप व अमेरिकी किसानों जैसी नहीं होती तब तक ये देश अपने कृषि बाजारों को सीधे वैश्विक अर्थ व्यवस्था में नहीं झोंक सकते। इस मामले में वर्तमान वाणिज्य मन्त्री श्री पीयूष गोयल का दिमाग भी पूरी तरह साफ है। उन्होंने भी अमेरिका को साफ कर दिया है कि भारत अपने किसानों व डेयरी उद्योग की हर हालत में सुरक्षा करेगा। ट्रम्प बेशक बार-बार यह बोलते रहें कि उन्होंने ही विगत मई महीने में हुए भारत-पाकिस्तान के सैनिक संघर्ष को रुकवाया मगर यह नहीं कह सकते कि वह भारतीय हितों को 'बलाए- ताक' रखकर हिन्दुस्तान से वाणिज्य समझौता करेंगे।

डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेशर पालिटिक्स

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की। यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रम्प ने भारत और रूस को 'मृत अर्थव्यवस्था' (डेड इकॉनमी) कहकर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया है। 7 अगस्त 2-25 से लागू होने वाले 25% टैरिफ का ऐलान करते हुए, ट्रम्प ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, ट्रम्प ने भारत के उच्च टैरिफ (जिसे उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक बताया) और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। यह टैरिफ अचानक भारत के लिए एक झटके के रूप में आया है, क्योंकि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे। ट्रम्प ने पहले 20-25% टैरिफ की संभावना जताई थी, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, रत्न और आभूषण, और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रम्प के 'मृत अर्थव्यवस्था' वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हां, ट्रम्प सही हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मुझे खुशी है कि ट्रम्प ने यह तथ्य सामने रखा। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और 'त्रुटिपूर्ण' जीएसटी को अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बताया। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रम्प के भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बार बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी। यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं और 25% टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे, जिससे मांग कम होगी और उत्पादन व रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार, एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'बुरे दिनों की शुरुआत' बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रम्प को 'व्हाइट हाउस का जोकर' कहकर उनकी आलोचना की।

सम्पादकीय...

मोदी, चीन और अमेरिका

आजकल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह सिल लिये हैं। बाकी मुद्दों पर तो वे हवा में तलवारबाजी कर भी ले रहे हैं, लेकिन अपने ही पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के उठाये सवालों पर चुप्पी साध ली है। कुछ इस मुहावरे के अंदाज में कि -हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं-। लेकिन स्वामी जी को इतना कम करके आंकना भी ठीक नहीं। स्वामी जी जिसके पीछे लगते हैं चाणक्य की तरह उसका सर्वस्व नाश भले न कर पायें पर उसकी तकलीफ बहुत बढ़ा देते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की जो तकलीफ बढ़ी हुई है उसकी जड़ में सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया और अदालत ले गये। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अदालतों में जो मुकदमे हैं वो भी सुब्रमण्यम स्वामी की ही देन है। ये अलग बात है कि इन दोनों ही मामलों में उनकी बंदरकूद के बावजूद कुछ खास नहीं हो पा रहा क्योंकि मामलों में ही दम नहीं है। लेकिन मोदी जी का मामला थोड़ा अलग है। जानकारों को पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका और कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहे हैं। इनको वहां के बारे में अच्छी-खासी जानकारी भी है। वे खुद भी कहते हैं कि वे वहां जब कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो उनकी वहां के कई लोगों से बातचीत होती थी। चीन को लेकर भी वे वैसा ही दावा करते हैं। तो वही सुब्रमण्यम स्वामी आजकल मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। वे एक से एक गंभीर आरोप मोदी जी पर लगा रहे हैं। पहले वे कहते थे कि मोदी के राज चीन के पास हैं, इसलिए मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते। फिर वे कहने लगे कि मोदी का राज अमेरिका के पास भी है, इसलिए मोदी ट्रंप का नाम नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने उनके खिलाफ एक फाइल तैयार की थी। वो तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गये इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब स्वामी एक कदम और आगे बढ़े हैं। वे कह रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटे तो उनका बाकी का जीवन सलाखों के पीछे जेल में गुजरेगा। ये आरोप कोई कम गंभीर नहीं हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी जी उधर ध्यान ही नहीं दे रहे। जबकि इसके उलट अगर कोई सोशल मीडिया पर मोदी जी या इनकी सरकार या बीजेपी की किसी सरकार के खिलाफ थोड़ा नकारात्मक भी लिख दे रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है और उसे जेल भेज दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि मोदी जी सुब्रमण्यम स्वामी के इतने गंभीर आरोपों पर चुप हैं ? क्या इसलिए कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं या कोई और बात है? बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए इनको माफ किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं लगता। क्योंकि यह सर्व विदित है कि मोदी जी के खिलाफ इस समय पार्टी यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की खूब चर्चा होती है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ ये बोल दिया, वो बोल दिया पर आपने ध्यान दिया होगा कि वे भी संकेतों में ही बात करते हैं। सीधे कभी मोदी या सरकार का नाम नहीं लेते। इसी तरह आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी देखा होगा। उन्होंने भी सरकार को बहुत सारे उपदेश दिये। परोक्ष तौर पर मोदी जी को भी बहुत सारे उपदेश दिये। लेकिन कभी खुलकर उनका या उनकी सरकार का नाम नहीं लिया। इससे पहले महाराष्ट्र के सांसद नाना पटोले ने जब एक बैठक में मोदी जी की आलोचना की तो उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट पर बात की। इसमें उन्होंने चीन को लेकर बात करते हुए कहा कि -लाल आंख किसको दिखाया? चीन को दिखाया? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। चीन को तो नहीं दिखाया। चीन को दिखाएगा तो वो बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तब तुमने जो भी किया, उसका वीडियो है मेरे पास। वो दे देंगे। आप जानते नहीं हम कितने चीन के निकट थे। इसके बारे में उनके पास इतने बड़े (हाथ से इशारा करते हुए) दस्तावेज हैं। पॉडकास्ट के पत्रकार ने पूछा क्या अमेरिका के पास भी दस्तावेज हैं? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हां हैं। इसीलिए तो ये दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। वो कहता...युद्ध विराम तो ये कहता है भाई युद्ध विराम...वो कहता दोनों बैठो तो ये हां भाई बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ। हम तो चीन और अमेरिका से अपने संबंध समझते थे। लेकिन अब तो वो हमारा नाम ही नहीं लेते। अब तो चीन और अमेरिका बस। सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उसका साफ-साफ मतलब यह निकलता है कि प्रधानमंत्री चीन और अमेरिका के द्वारा ब्लैक मेल किये जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। अब यहां सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है। बल्कि 143 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री का है। यह मामला अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से बहुत आगे बढ़कर देश के हित को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला बन गया है। अभी तक माना जाता था कि जो भी नीतियां केंद्र सरकार बनाती है वह इस देश की कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित को ध्यान में रखकर बनाती है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार चीन और अमेरिका से ब्लैक मेल होने के दबाव में ऐसे फैसले ले रही है। आखिर मोदी जी की कौन सी फाइल चीन और अमेरिका के पास है ? कौन सा उनका वीडियो दोनों देशों के पास है? प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी को सामने आना चाहिए। बोलना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई वीडियो या दस्तावेज चीन, अमेरिका के पास है भी तो भी मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। वो देश के हैं। देश के लोग उनके अपने हैं। अपनी बात अपने लोगों के सामने रखनी चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर हुई है तो देश के लोग उसे माफ करेंगे और चीन और अमेरिका के सामने खुद खड़े होंगे। आखिर अगर कोई महिला या अपराधी गैंग किसी का आपत्ति जनक वीडियो बना लेता है या कोई फाइल उसके खिलाफ तैयार कर लेता है तो वह व्यक्ति क्या करता है ? डरता है तो ब्लैक मेल होता है और हिम्मत दिखाता है तो वह पुलिस के पास जाता है। साइबर सेल के पास जाता है। ऐसे अपराधियों को पकड़वाता है। अगर चीन और अमेरिका ब्लैक मेल कर रहे हैं तो वो भी किसी अपराधी से कम नहीं हैं। मोदी जी को देश की जनता के सामने आना चाहिए, चीन और अमेरिका का डट कर मुकाबला करना चाहिए। देश के 143 करोड़ लोग उनका साथ देंगे। मुझे इसमें रत्ती

गोडसे कौन?, हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद ना भवति!

राजेंद्र शर्मा

गोडसे कौन था? वही नाथूराम गोडसे। वही नाथूराम गोडसे जिसे महात्मा गांधी की हत्या के लिए फांसी की सजा दी गयी थी। शायद हमसे शुरू से ही गलती हो रही है। हम गोडसे का नाम इस तरह कैसे ले सकते हैं नाथूराम गोडसे? गोडसे नाम के आगे जी तो लगाया ही जाना चाहिए था। यह अमृत काल है। राम राज्य भी आ चुका है। पुरानी वाली आजादी के बाद लिखा गया झूठा इतिहास बदला जा रहा है। जिन देशभक्तों को पिछले इतिहास में भुला दिया गया था, उन्हें याद किया जा रहा है। जिन देशभक्तों को लोगों की नजरों से छुपा दिया गया था, उन्हें खोजा जा रहा है। सावरकर जी का वीरत्व स्थापित किया जा चुका है। अब चेले, गोडसे जी की देशभक्ति साबित किए जाने की बारी है। साध्वी प्रज्ञा ने तो कई साल पहले ही एलान कर दिया था कि अगर गांधी देशभक्त थे, तो गोडसे भी देशभक्त थे। कितनी सही बात है। एकदम समदर्शितापूर्ण। दोनों देशभक्त। अपने-अपने तरीके से दोनों देश की सेवा में रत। क्या हुआ कि एक देशभक्त ने दूसरे देशभक्त को गोली मार दी। एक नहीं तीन गोलियां मारीं, मगर उससे भी क्या? गोलियां खाने वाला देशभक्त मर गया, उससे भी क्या? था तो आखिरकार, दो देशभक्तों के बीच का मामला ही। देशभक्त भी ऐसे-वैसे नहीं, अंग्रेजों के जमाने वाले। हमें क्या अधिकार है दो देशभक्तों के झगड़े में टांग अड़ाने का? हमें क्या अधिकार है, किसी को हत्यारा और किसी को मकतूल कहने का? हमें क्या अधिकार है, किसी को खलनायक और किसी को शहीद मानने का? इस मसले का निपटारा अब हो ही जाना चाहिए। अमृतकाल में इसका निपटारा अब और लटका नहीं रहने दिया जा सकता। देखा नहीं कैसे अमित शाह के संसद में इसका एलान करने भर की देर थी कि 'हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है', सेकुलर बिरादरी ने जवाब के नाम पर नाथूराम गोडसे को आगे कर दिया है। उस पर कह रहे हैं कि अमित शाह की बात तो गलत हो नहीं सकती, अभी-अभी कथावाचक, प्रदीप मिश्र ने उन्हें शंकर का अवतार घोषित किया है। जरूर हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता होगा। जरूर हिंदुओं में कोई

मैन्यूफैक्चरिंग फॉल्ट होगा, जो उन्हें आतंकवादी बनने से रोकता होगा। शंकर के अवतार से बेहतर यह बात और कौन जान सकता है? फिर इससे तो मोदी जी भी असहमत नहीं हो सकते हैं, जो पहले ही विष्णु के अवतार घोषित हो चुके हैं। अब बस योगी जी ब्रह्मा के अवतार घोषित हो जाएं, फिर तो हिंदुओं के आतंकवादी नहीं हो सकने पर महा-त्रयी की ही मोहर लग जाएगी। इसमें अगर कोई देरी हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि योगी जी की उम्र, ब्रह्मा जी से मैच नहीं खाती है। दाढ़ी भी नहीं है। और मोदी जी विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच अदला-बदली करने के लिए तैयार होने से रहे। खैर! सेकुलरवाले हुज्जत कर रहे हैं कि शाह जी कहते हैं, तो गोडसे कौन था? हिंदू था या महात्मा गांधी की हत्या करने वाला आतंकवादी था? अब हिंदू था तो हत्यारा आतंकवादी हो नहीं हो सकता। और हत्यारा आतंकवादी था, तो हिंदू नहीं हो सकता। तब गोडसे था कौन?

इस सवाल का जवाब जरूरी है, वर्ना गोडसे की गोली से गांधी का सीना छलनी हुआ सो हुआ, शाह जी का अवतारत्व भी छलनी हो जाएगा! अवतार शंकर का और वचन सरासर झूठे! वैसे गोडसे और गांधी का यह पूरा किस्सा सच ही है, इसकी क्या गारंटी है? यह किस्सा पुरानी आजादी के टैम का है। उसमें भी नेहरू के राज का। माना कि सरदार पटेल भी इस किस्से की तस्दीक करते थे। सिर्फ तस्दीक ही नहीं करते थे, उन्होंने तो इसे सच मनवाने के चक्कर में, आरएसएस जैसे सच्चरित्र संगठन पर पाबंदी ही लगा दी थी। उनका तो कहना था कि गोली भले गोडसे ने चलायी हो, पर कारतूस में बारूद सावरकर और गोलवलकर के लोगों ने भरा था। पर इसका तो कोई प्रमाण नहीं है कि यही सरदार पटेल के वास्तविक विचार थे। बेचारे सरदार भी क्या करते? नेहरू पीएम बन बैठे और सरदार नंबर-दो रह गए।

मामूली गृहमंत्री। बेचारे को नेहरू की हर बात माननी पड़ती थी। उनकी तबियत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। नेहरू ने कहा गोडसे ने गांधी को मारा था, सरदार को भी हां में हां मिलाकर कहना पड़ा कि गोडसे ने ही गांधी को मारा था।

सारी दुनिया को भी यही मानना पड़ा कि गोडसे ने गांधी को मारा था। और जो आरएसएस देश-दुनिया को बता सकता था कि गोडसे हिंदू था और हिंदू आतंकवादी हत्यारा नहीं हो सकता है, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। सच को दबा दिया गया। हिंदू को आतंकवादी हत्यारा बना दिया गया। लेकिन, अब और नहीं। दूसरी आजादी के बाद नहीं। अमृत काल में नहीं। आज नहीं तो कल, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में सच सामने आ ही जाएगा। दुनिया को पता चल ही जाएगा कि गोडसे ने गांधी को नहीं मारा था। गोडसे गांधी को मार ही नहीं सकता था। गोडसे हिंदू था और हिंदू आतंकी हत्यारा हो ही नहीं सकता। गांधी को किसी और ने मारा होगा और तुष्टीकरण के लिए नेहरू ने गोडसे का नाम लगा दिया, जो एक हिंदू था। वैसे शोध का विषय तो यह भी है कि क्या गांधी को वाकई गोली ही लगी थी? इस पर तो खैर काफी राष्ट्रवादी शोध कर भी चुके हैं कि गोली खाकर गिरते-गिरते गांधी के आखिरी शब्द ''हे राम'' नहीं थे। जय श्रीराम तो बिल्कुल ही नहीं थे। उनके आखिरी शब्द थे, ''हाय राम'', जो अचानक चोट लगने पर किसी भी साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है।वैसे हो तो यह भी सकता है कि गांधी की हत्या के लिए गोडसे पर दोष मढ़ना, एक गहरे हिंदू-विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा रहा हो। जरूर इसके पीछे मकसद बाद में हिंदुओं को आतंकवादी कहकर बदनाम करना होगा। और यह भी कि असली आजादी के बाद जब अमित शाह यह कहें कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो उनकी बात काटने के लिए गोडसे का नाम लिया जा सके। पर अब यह झूठ और नहीं चलेगा। अब तो अदालतों ने भी मानना शुरू कर दिया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। मालेगांव केस में तभी तो साध्वी प्रज्ञा समेत सब छूट गए। वह दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर गांधी केस चलाया जाएगा और गोडसे को बाइज्जत बरी कर सारी दुनिया से मनवाया जाएगा कि हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद ना भवति।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लोक लहर के संपादक हैं।)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पॉकेट/फेस एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

सेना पर टिप्पणी का मामला: आपको कैसे पता चीन ने 2000 किमी जमीन कब्जा ली सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

नई दिल्ली । भारत-चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है. 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने यह विवादित वक्तव्य दिया था. इसे लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने पहुंचे राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली क्या आप वहां थे आपके पास क्या सबूत था अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बात नहीं कह सकते. जब सीमा पर झड़प की स्थिति

हो, तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं. 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत-चीन विवाद पर टिप्पणी की थी. राहुल ने एक भाषण में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं. इस बयान को आधार बना कर बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा

लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट में दाखिल शिकायत में श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर 2022 को आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही चीनी सेना को हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. इसके बाद चीनी सेना वापस लौट गई. इसके बावजूद राहुल गांधी ने सेना को अपमानित करने वाला झूठा बयान दिया. इससे उन्हें और भारतीय सैनिकों को धक्का लगा है. इस केस को राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता मामले में प्रभावित पक्ष नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सेना का सम्मान करता हो, वह ऐसे बयान से पीड़ित हो सकता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा है. इसके नाम पर कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में राहुल की तरफ से जिरह करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. इस पर जजों ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह दलील हाई कोर्ट में नहीं दी गई थी. सिंघवी ने स्वीकार किया कि हाई कोर्ट में यह बात नहीं उठाई गई थी.

सिनेमाघरों और ओटीटी के लिए दोहरे मानदंड—आमोद के. कंठ

राजीव गांधी हत्याकांड पर बनी वेब सीरीज को लेकर CBI अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली (साहिल गौड़)प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के पूर्व डीआईजी (जांच) श्री आमोद के. कंठ ने Sony LIV पर प्रसारित वेब सीरीज द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस सीरीज में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है और विशेष जांच दल (SIT) के अधिकारियों को बदनाम किया गया है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक जांच में अहम भूमिका निभाई थी।

प्रेस वार्ता की शुरुआत प्रयास संस्था के मीडिया प्रमुख अमिताभ श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि समय के साथ सिनेमा का स्वरूप बदला है—1950 के दशक की मुगल-ए-आजम से आज की पीढ़ी सायरा जैसे कंटेंट को मोबाइल और ओटीटी पर देख रही है। कोरोना के बाद ओटीटी कंटेंट घर के हर सदस्य की पहुंच में है, लेकिन इस पर कोई ठोस नियामक नियंत्रण नहीं है।

श्री आमोदे कंठ, जो 23 मई 1991 को सबसे पहले राजीव गांधी हत्याकांड के घटना स्थल पर पहुंचने वाले सीबीआई अधिकारी थे, ने बताया कि कैसे इस वेब सीरीज में उनकी और उनके साथियों की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है। ÷हमारे वास्तविक नामों का इस्तेमाल किया गया, झूठे घटनाक्रमों को दिखाया गया, हिरासत में उत्पीड़न और महिला आतंकवादी की गिरफ्तारी के आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए—ये सब बिना हमारी अनुमति के

किया गया,÷उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि निर्माता नागेश कुकुनूर ने एक साक्षात्कार में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्हें असली घटनाओं की सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर %थ्रिल% के लिए कहानी में फेरबदल किया। ÷अगर कोई निर्माता सच्चाई जानते हुए भी उसे न दिखाए, तो वह रचनात्मकता नहीं बल्कि दुष्प्रचार है,÷ श्री कांत ने दो टूक कहा।

उनकी बात का समर्थन करते हुए मेजर जनरल माणिक सबरवाल, जो उस समय हस्त बम डिस्पोजल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे, ने तकनीकी जांच का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने विस्फोटक सामग्री—बॉल बेयरिंग, तार, टॉगल स्विच और आत्मघाती बनियान—का फोरेंसिक विश्लेषण किया और पाया कि यह सिंगापुर फैगमेंटेशन ग्रेनेड था जिसे ड्यूल टॉगल स्विच और 9-वोल्ट बैटरी से चालू किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जांच कंठ की टीम के सहयोग से हुई थी, न कि उस व्यक्ति द्वारा जैसा कि सीरीज में झूठा दर्शाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजन राज, जिन्होंने श्री कंठ की ओर से मानहानि का मुकदमा दायर किया है, ने कहा कि यह सीरीज केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं, बल्कि सीबीआई जैसी संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा, ÷जब रचनाकार असली नाम और घटनाओं का उपयोग करते हैं, तो उन पर यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे डॉक्यूमेंट्री जैसी सटीकता बरतें, न कि कल्पना के नाम पर झूठ फैलाएं।÷

उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियामक निगरानी की कमी को भी उजागर किया और कहा कि यह समय है जब न्यायपालिका रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमाएं तय करे। ÷इस तरह की झूठी सामग्री से न सिर्फ सार्वजनिक धारणा विकृत होती है, बल्कि यह राष्ट्रीय अखंडता को भी प्रभावित कर सकती है।÷

श्री दिलीप शरण, जो एक खेल मीडिया चैनल के पूर्व ब्यूरो हैं, ने भी रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमाओं पर स्पष्ट नियम बनाने की मांग की। उन्होंने 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि जिस प्रकार भ्रामक विज्ञापन दंडनीय हैं, उसी प्रकार असत्यापित मीडिया कंटेंट पर भी अंकुश लगना चाहिए।

उन्होंने कहा, ÷श्री कंठ जैसे अधिकारियों की वर्षों की सेवा और संस्थागत विश्वास को इस तरह की झूठी कहानियों से नुकसान पहुंचाना न केवल अनुचित है बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है।

इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और यह प्रश्न उठाया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिल्मों और ओटीटी कंटेंट को लेकर दोहरे मानदंड क्यों अपना रहा है, जब कि ओटीटी पर बच्चों के लिए भी आपत्तिजनक सामग्री एक बटन की दूरी पर उपलब्ध है।

प्रेस वार्ता का समापन करते हुए श्री कंठ ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ें, जिसमें पूरे मामले का सच्चा और क्रमबद्ध विवरण दर्ज है। ÷हमने कानून के अनुसार ईमानदारी से जांच की, उस ऐतिहासिक जांच को सनसनीखेज झूठ से बदनाम न करें।

55 साल बनाम 11 साल- कांग्रेस ने गरीबों को सपने दिखाए, जबकि डबल इंजन सरकार ने उन्हें साकार किया : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश और प्रदेश के गरीबों के लिए ठोस कार्य नहीं किए। कांग्रेस के शासन-काल में गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होता चला गया, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने जनकल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारकर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के लाभार्थियों को आवंटन पत्रों के वितरण तथा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अंतरिम मल्कीयत प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों को प्लॉट देने के नाम पर सिर्फ सपना दिखाया, न ही उन्हें कागजात दिए गए और न ही कब्जा मिला। इसके विपरीत, वर्तमान राज्य सरकार ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट के कागजात और कब्जा देकर उनका सपना साकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतरती थीं। जब चुनाव आते थे, तभी घोषणाएं होती थीं। 2014 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचता था। महिलाएं लकड़ी के धुएं में परेशान रहती थीं, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने कभी उनकी चिंता नहीं की। लोगों को गैस सिलेंडर के लिए 4-4 दिन तक लाइनों में लगना पड़ता था। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घरों में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। अभी तक 18 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में क्या स्थिति थी, वो सब जानते हैं। महिलाओं को कितनी तकलीफें उठाकर 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था, लेकिन 55 साल तक शासन करने वाले नेताओं ने महिलाओं की इस पीड़ा को कभी नहीं समझा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था कर महिलाओं को बहुत बड़ा लाभ दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने 55 साल तक शासन किया, वे आज गरीबों के हितों की बात कर रहे हैं। वे जनता को गुमराह करने के लिए झूठ प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से संविधान को खतरा है। जबकि सच्चाई यह है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस को खतरा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने 55 वर्षों में जनकल्याण के लिए कौन से कार्य किए। वे सिर्फ झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग सेवाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गरीब व्यक्ति का बैंक खाता भी नहीं खुलता था। उन्हें दो खाताधारकों के हस्ताक्षर लाने होते थे, जो अवसर मना कर देते थे, कितना अपमान गरीब व्यक्ति को सहन करना पड़ता था। इसका जिम्मेदार अगर कोई था तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जन-धन खाते खोलकर आज गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछते हैं कि जन-धन खाते खुलवा दिए, लेकिन इनमें पैसा कौन जमा करेगा। उनको ये बात सुनकर हैरानी होती है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वे जनधन खातों के आंकड़े देख लें, जिनमें पिछले 11 वर्षों में गरीबों ने अपनी मेहनत की बचत जमा की है। ये गरीब का वो संकल्प है जिसको श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की पीड़ा और गरिमा का हमेशा मजाक उड़ाया है। एक समय था जब माताओं-बहनों को शौच के लिए सूरज उगने का इंतजार करना पड़ता था। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी प्राथमिकता नहीं दी।

लक्ष्मी नगर ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक में जोश, संगठन को मज़बूत करने का लिया गया संकल्प

नई दिल्ली (ए के चौधरी)लक्ष्मी नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन स्थानीय ने ब्लॉक क्षेत्र में उत्साहपूर्वक किया गया। यह बैठक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नवचेतना का संचार करने, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता से जुड़ाव को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस प्रभारी श्री नईम मलिक ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि ÷आज के दौर में कांग्रेस पार्टी को फिर से जनता की पहली पसंद बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना, युवाओं को जोड़ना और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।÷ उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस के विचारों को हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचाएं।

बैठक में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री सुमित शर्मा ने भाजपा सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता से झूठे वादे कर विश्वासघात किया है। चुनावों से पहले जो सपने दिखाए गए थे, वे अब टूट चुके हैं। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को उजाड़ने का असंवेदनीय प्रयास भाजपा की असली नीयत को उजागर करता है। कांग्रेस हमेशा से बच्चों, गरीबों और मजलूमों की आवाज़ रही है और आगे भी रहेगी।÷

वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि ÷अब वक्त आ गया है कि हम घर-घर जाकर उन पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक बार फिर कांग्रेस की मुख्यधारा से जोड़ें जो किसी कारणवश पार्टी से दूर हो गए थे। राहुल गांधी जिस तरह जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, उसी जोश और जज्बे के साथ हमें भी सत्ता के गलियारों तक जनता की आवाज़ पहुंचानी होगी। हमें जनसंघर्ष का रास्ता अपनाकर सरकार को जवाबदेह बनाना होगा।÷

इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री अभिषेक कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी दीपक कुमार गुप्ता तथा कार्यकर्ता इमरान अमीन ने भरोसा दिलाया कि ÷लक्ष्मी नगर में कांग्रेस को पुनः मजबूत बनाने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए यदि सड़कों पर भी उतरना पड़े तो कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे।

जनआंदोलन की शुरुआत यहीं से होगी।÷

बैठक में भानु सहित कांग्रेस परिवार के अन्य समर्पित कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि आज का यह दौर संगठन को फिर से खड़ा करने और जनता का भरोसा जीतने का है।

बैठक में पारित प्रमुख प्रस्तावों में शामिल थे-

संगठनात्मक ढांचे को ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूत करना

सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना

युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से संगठन से जोड़ने के लिए अभियान चलाना भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जनजागरण अभियान

अंत में, सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व और जनसंघर्ष की परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करेंगे।

शिबू सोरेन ने जल, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया: खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर सोमवार को शोक व्यक्त करते हुए कहा कि झामुमो नेता ने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार तथा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया। खरगे ने सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात करके उन्हें ढांढस बंधाया। शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन जी के निधन से मैं दुःखी हूं। उन्होंने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया।'' उन्होंने कहा, ''मैंने उनके सुपुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात कर उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। दुःख की इस घड़ी में ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे।'' कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर 'पोस्ट' कर कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन सिर्फ सांसद और तीन बार मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि ठीक 25 साल पहले झारखंड के निर्माण के लिए चलाए गए आंदोलन में वह निर्णायक भूमिका में थे। उन्होंने कहा, ''वह सचमुच एक महान व्यक्ति थे जिनका सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति जुनून प्रेरणादायक था। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम, 2006 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के निर्माण में भारी योगदान दिया।

जहांगीरपुरी में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, अस्पताल ले गए दोस्त हुए फरार

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक युवक की पहचान, रोहित बरार (20 वर्ष) के रूप में हुई है. वह रोहिणी सेक्टर-16 के सरदार कॉलोनी के रहने वाला था. बताया जा रहा है कि, गोली रोहित के बाएं कंधे के नीचे लगी थी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में रोहित को उसके तीन दोस्त पंकज उर्फ पंखा, आलम और आकाश बीजेआरएम अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया. हैरान करने वाली बात यह रही कि, अस्पताल पहुंचने के बाद रोहित के तीनों साथी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए. पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार दिन की है, जब जहांगीरपुरी ब्लॉक में एक युवक को गोली मारे जाने की सूचना पीसीआर कॉल से पुलिस को मिली थी. लेकिन किसने और क्यों गोली चलाई, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है. वहीं, अस्पताल से फरार हुए मृतक के दोस्त भी पुलिस के संदेह के घेरे में है.अभी तक इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी भी सामने नहीं आया है और जिस तरह से रोहित के साथी उसे घायल अवस्था में अस्पताल छोड़ने के बाद भाग निकले, उससे इस यह पूरा मामला और भी रहस्यमय और उलझा हुआ लग रहा है. पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को खंगालने के साथ मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की भी जांच की. पुलिस के अनुसार घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेजों में संदिग्ध नजर आ रहे हैं और जिस तरह से युवक की हत्या की गई है उसके मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. अंदेशा है कि, रोहित के साथ कुछ और भी लड़के थे, जिनमें से ही किसी ने उसकी हत्या की है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की गहनता के साथ जांच में जुटी हुई है और फरार युवकों की तलाश में दबिश डाल रही है.

बोधगया मंदिर कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को रद्द करने और उसकी जगह एक केंद्रीय कानून लाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति दी। इस कानून का मकसद बिहार स्थित महाबोधि मंदिर का सही नियंत्रण, प्रबंधन और प्रशासन सुनिश्चित करना है। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार के बोधगया में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याचिका में 1949 के कानून की वैधता को भी चुनौती दी गई है। मामला जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि इसी तरह की मांग वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। यह याचिका अब लंबित मामले के साथ ही सुनवाई के लिए जोड़ दी गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1949 का अधिनियम असांविधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 13 के खिलाफ है। अनुच्छेद 13 उन कानूनों से संबंधित है, जो मूल अधिकारों के विपरीत हैं या उन्हें कमजोर करते हैं। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर में हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों की आस्था के हित में मंदिर का प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन केवल बौद्धों के माध्यम से ही होना चाहिए। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 1949 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। और याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। 1949 का यह अधिनियम महाबोधि मंदिर के बेहतर प्रबंधन से संबंधित है। महाबोधि मंदिर परिसर में एक 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर, वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान से जुड़े छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं। इनके चारों ओर कई प्राचीन स्तूप हैं और यह पूरा क्षेत्र तीन स्तरों की घेराबंदी से सुरक्षित है। एक सातवां पवित्र स्थान कमल सरोवर इस घेरे के बाहर दक्षिण दिशा में है। मंदिर क्षेत्र और कमल सरोवर के चारों ओर दो या तीन स्तरों पर परिक्रमा मार्ग बने हुए हैं। यह पूरा स्थल आसपास की भूमि की तुलना में लगभग 5 मीटर नीचे स्थित है।

मंदिर का पैसा आपकी जेब में क्यों जाए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल

नई दिल्ली। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कर रही है. इन याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसके मुताबिक मंदिर से जुड़ी व्यवस्था राज्य सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया है.
याचिकाओं में कहा गया है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है. इस अध्यादेश के ज़रिए मंदिर पर सरकार अपरोक्ष रूप से अपना नियंत्रण करना चाह रही है.
सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं की पैरवी करते हुए निजी मंदिर होने की दलील दी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर की आय सिर्फ आपने लिए नहीं बल्कि मंदिर विकास योजनाओं के लिए भी है. श्याम दीवान ने कहा कि हम सरकार की योजना पर एकतरफा आदेश को चुनौती दे रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि अदालत ने मुद्दे तय कर दिए हैं, जिनमें सरकार द्वारा ट्रस्ट का अधिग्रहण भी शामिल है. याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने कहा कि राज्य ज़मीन खरीदने के लिए मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करना चाहती हैं. कोर्ट ने कहा कि राज्य का इरादा मंदिर के धन को हड़पने का नहीं लगता, वे इसे मंदिर के विकास पर खर्च कर रहे हैं.
श्याम दीवान ने कहा कि सरकार हमारे धन पर कब्जा कर रही है मेरा मंदिर एक निजी मंदिर है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान से पूछा कि आप किसी धार्मिक स्थल को निजी कैसे कह सकते हैं. जहां बहुत से श्रद्धालु आते हैं, वह निजी नहीं हो सकता. प्रबंधन निजी हो सकता है, लेकिन कोई देवता निजी कैसे हो सकता है श्याम दीवान ने कहा कि यह एक अलग मुद्दा है. किसी दीवानी मुकदमे में, जिसमें मैं पक्षकार नहीं हूं, राज्य मेरी पीठ पीछे आकर आदेश ले लेता है. उनके पास कोई योजना हो सकती है. लेकिन क्या सरकार ये कर सकती हैं जो उन्होंने इस योजना के लिए किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का पैसा आपकी जेब में क्यों जाए वे इसका इस्तेमाल विकास के लिए क्यों नहीं कर सकते श्याम दीवान ने कहा कि यह एक अलग मुद्दा है. लेकिन यह इस अदालत की वंचित प्रक्रिया का मामला है. मेरी बिना जानकारी के अदालत से आदेश हासिल किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि मंदिर परियोजना प्रशासन समिति में हाईकोर्ट के रिटायर जज और जिलाधिकारी भी शामिल होंगे. गोस्वामी समाज के नुमाइंदे भी होंगे. ऑर्डिनेंस की संवैधानिकता पर बाद में विचार करेंगे. अब इस पर कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई होगी.
कोर्ट ने कहा कि रिलिजियस टूरिज्म आज का सबसे लोकप्रिय उद्योग है. इंफ्रा और रोजगार दोनों का जन्मदाता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि शिरडी, पुत्तपर्थी, तिरुपति, अमृतसर को देखें, कैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. कोर्ट ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, स्थान की पौराणिकता और धरोहरों को सुरक्षित रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बांके बिहारी कॉरिडोर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए समिति गठित करने के पक्ष में है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि अध्यादेश लाने की इतनी जल्दी क्या थी. जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि भगवान कृष्ण पहले मध्यस्थ थे, मामले में मध्यस्थता करने का प्रयास हो. मंदिर के धन का उपयोग तीर्थयात्रियों के लिए किया जाना चाहिए, इसे निजी व्यक्ति अपनी जेब में नहीं डाल सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश की संवैधानिकता की जांच पहले हाईकोर्ट को करनी चाहिए. यदि राज्य सरकार कोई विकास कार्य करना चाहती थी, तो उसे कानून के अनुसार ऐसा करने से किसने रोका ज़मीन निजी है या नहीं, इस मुद्दे पर अदालत फ़ैसला सुना सकती है. राज्य सरकार गुपचुप तरीके से आ रही है, उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दे रही, हमें इसकी उम्मीद नहीं है. राज्य को पूरी निष्पक्षता से उन्हें सूचित करना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के रिटायर जज या वरिष्ठ सेवानिवृत्त जिला जज को प्रबंधन ट्रस्टी बनाएंगे. हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अंतरिम समिति को धनराशि का उपयोग करने के लिए कुछ समय देंगे - भक्त आएं और दान करें, इसका कुछ हिस्सा खर्च किया जाए.

सीएम योगी बोले- आतंक को संरक्षण देती है सपा और कांग्रेस, कोर्ट के हालिया फैसले इसका सबूत

सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विकास के लिए भी संकल्पित है। विरासत के संरक्षण के लिए मां शाकंभरी देवी कॉरिडोर बन रहा है। किसी भी मौसम में देशभर के श्रद्धालु आ सकते है। इसी तरह महाकुंभ में इतने श्रद्धालु आए, इससे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल परेशान हैं। उन्हें परेशानी यह हो रही है कि सनातन धर्म का वैभव इतना ऊपर क्यों हो रहा है। उन्हें भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं हो रही है। कांग्रेस और सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकी वारदात होती है तो यह संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। हाल ही में दो घटनाओं पर न्यायालय ने निर्णय दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हिंदुओं को अभियुक्त बनाया था, जिसके खुलासे अब हो रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ अपराध था। कांग्रेस आतंकी हमला करने वालों को क्लीन चिट देती है और सुरक्षा बलों के पराक्रम पर सवाल खड़ा करती है।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य को राहत, हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और गिरफ्तारी के खिलाफ मांगी गई व्यक्तिगत राहत के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रुख करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया। ईडी की जांच, गिरफ्तारी आदि की शक्तियों से संबंधित पीएमएलए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले दोनों के संबंध में, शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर करने को कहा, जिस पर 6 अगस्त को विचार किया जाएगा। ईडी के अनुसार, इस घोटाले

से राज्य के खजाने को 2,161 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। कथित अवैध सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के ज़रिए संचालित होता था, शराब बनाने वालों से रिश्वत लेता था और बदले में उन्हें बाजार में हिस्सेदारी देता था। सरकारी दुकानों के ज़रिए देशी शराब की ऑफ-द-बुक बिक्री, विदेशी शराब व्यापार के लिए एफएल-10ए लाइसेंस में हेराफेरी, और कार्टेल जैसी बाज़ार प्रथाओं का कथित तौर पर अपराध की भारी कमाई को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने इस घोटाले में अनवर ढेबर और पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा सहित कई प्रमुख लोगों को नामजद किया है।
साथ ही, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर नियमित रूप से रिश्वत मिलती थी। अब तक, इस मामले में 205 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की खुली कार्रवाई करार दिया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है. नीतीश कुमार ने प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति में बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है. इसके लागू होने के बाद अब बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी. नीतीश कुमार ने एक एक्स पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया है. बिहार में काफी समय से इस नीति को लागू किए जाने की मांग की जा रही है. नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में कहा, नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं.
शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है. नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा. वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा. TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है. इस नीति का लाभ बिहार के स्थानीय लोगों को मिलेगा. इसके तहत अब बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य राज्यों से आने वाले युवाओं की जगह बिहार के युवाओं को वरीयता दी जाएगी. प्रदेश में इस नीति को लागू करने की लगातार मांग की जा रही थी. हाल ही में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे. इस आंदोलन में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया और सरकार से मांग की कि वो इस नई नीति को बगैर समय गंवाए लागू करे.

राज्य का दर्जा कब लौटाएंगे केंद्र से फारूक अब्दुल्ला का सवाल, बोले- जम्मू-कश्मीर के लिए क्या किया

जम्मू। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के छह साल पूरे होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय-सीमा के बारे में पूछा। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर अपना वादा पूरा करने का आरोप लगाते हुए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने और लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने के अधिकार से वंचित न करने का आग्रह किया। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे राज्य का दर्जा कब लौटाएंगे उन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव होंगे और सरकार बनेगी, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
उसका क्या हुआ अब वे कह रहे हैं कि वे दो खाली विधानसभा सीटों पर चुनाव कराएंगे, लेकिन राज्यसभा की चार सीटों के चुनावों का क्या वे लोगों को सदन में जाकर अपनी समस्याएं बताने के अधिकार से क्यों

वंचित कर रहे हैं अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जश्न मनाने के लिए भाजपा द्वारा कुछ कार्यक्रमों की योजना बनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ एनसी नेता ने कहा कि भाजपा के पास जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए। अब्दुल्ला ने कहा, उनके पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने (भाजपा ने) इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए छह सालों में क्या किया हमारे उच्च शिक्षित लड़के-लड़कियाँ बेरोजगार हैं। महंगाई आसमान छू रही है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। क्या यही उनकी उपलब्धि है मुझे यकीन है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा; कोई रास्ता नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, -उनके वायसराय यहीं राजभवन में बैठे हैं। जम्मू-कश्मीर में एक सरकार है, लेकिन वायसराय ही मुख्य व्यक्ति है। समय आ गया है जब इसे बदलना होगा। यह एक लोकतांत्रिक देश है। घाटी में शांति सुनिश्चित करने के केंद्र के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर, अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे शांति आती नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि हम यह सोचकर मूर्खता की दुनिया में जी रहे हैं कि शांति रातोंरात आ जाएगी। हमारा एक मज़बूत पड़ोसी है, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान। किसी न किसी तरह, हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। युद्ध कोई रास्ता नहीं है। अंत में, आपको कलम उठाकर बातचीत करनी ही होगी। इससे हमें क्या नुकसान होगा।

एसआईआर को लेकर संसद में हंगामा जारी, शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा मंगलवार तक सस्पेंड

नई दिल्ली।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक मिनट का मौन रखा गया। वहीं, विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों की तरह सोमवार को भी लोकसभा में हंगामा किया। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए फिर से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 पेश करने का प्रयास किया, विपक्ष ने सदन में अपना विरोध जारी रखा और दिन भर की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के नारे लगाने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज सदन की स्थिति देखकर मुझे दुख हुआ।

सभी दलों ने मिलकर राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने का फैसला किया था। विपक्ष के अनुरोध पर, हम इन विधेयकों पर चर्चा के लिए दो दिन आवंटित करने पर सहमत हुए। अब जब हम खिलाड़ियों के लिए यह महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं, तो विपक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है... खेल मंत्री भी चर्चा के लिए तैयार हैं... आप न केवल वह नहीं कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं, बल्कि सदन का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 10 वर्ष के दौरान 17 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरियां तथा रोजगार मिले, वहीं विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पांच साल में चार करोड़ से अधिक रोजगार निर्माण की योजना है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सोरेन के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के निमरा गांव में जन्मे सोरेन ने वहीं के गोला हाईस्कूल से मैट्रिक तक की शिक्षा ली। उन्होंने कहा कि पेशे से किसान सोरेन जाने माने आदिवासी नेता थे। हरिवंश ने कहा, ''दिशोम गुरू कहे जाने वाले सोरेन आम लोगों के बीच गुरुजी के नाम से लोकप्रिय थे। सोरेन जमीनी कार्यकर्ता थे जिनकी झारखंड राज्य के लिए हुए आंदोलन में अहम भूमिका थी।''

उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी, कई इलाके हुए जलमग्न

नई दिल्ली। देशभर में मॉनसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जबकि वाराणसी समेत अन्य शहरों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना में आई बाढ़ के कारण फतेहपुर जिले में कानपुर-बांदा मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। किशुनपुर-दांदे यमुना पुल का संपर्क मार्ग टूट जाने से इस रास्ते से आवागमन भी बंद हो गया है। अब तक 200 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं और हजारों एकड़ खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। नदियों के तेज बहाव की चपेट में आकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

बिहार और बिहारियों के अधिकारों पर हुआ हमला

पटना। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को भाजपा और भारतीय चुनाव आयोग पर निशाना साधा, जब चुनाव आयोग ने राजद नेता तेजस्वी यादव को उनके EPIC कार्ड का विवरण मांगने के लिए नोटिस भेजा। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को संदिग्ध आयोग (संदिग्ध आयोग) कहा।

भाजपा और मोदी जी भ्रम पैदा करते है

पत्रकारों से बात करते हुए, सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा और मोदी जी भ्रम पैदा करते हैं। क्या

चुनाव आयोग अलादीन का चिराग है नोटिस भेजकर वे क्या करेंगे चुनाव आयोग अपने आप में एक %संदिग्ध आयोग है। वे हर हाल में भाजपा के प्रवक्ता हैं। चुनाव वाले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए

चुनाव आयोग एक संदिग्ध आयोग, बीजेपी के इशारे पर कर रहा काम, तेजस्वी को नोटिस जारी करने पर भड़के पप्पू यादव

चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए, पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग बिहार के लोगों के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा, जिस तरह से भाजपा और चुनाव आयोग ने पिछले दरवाज़ों से एसआईआर पर हमला किया है, उससे बिहार और बिहारियों के अधिकारों पर हमला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेता 10 अगस्त से बिहार का दौरा शुरू करेंगे। यादव ने कहा, तो, 10 अगस्त से राहुल गांधी और महागठबंधन साथ होंगे, और कटिहार तक दौरे होंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के मसौदे को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम सूची से गायब है और उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर बदल दिया गया है। इस दावे का खंडन करते हुए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी का नाम मतदाता सूची के मसौदे में क्रमांक 416 पर शामिल है।

दिल्ली पुलिस के पत्र पर भड़कीं ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने दिल्ली पुलिस पर बांग्ला को कथित तौर पर बांग्लादेशी कहने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर बंगाली भाषी लोगों का अपमान और अपमान करने के लिए संविधान-विरोधी भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। तृणमूल प्रमुख ने कथित तौर पर लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा लिखा गया एक पत्र साझा किया, जो दिल्ली के बंग भवन को संबोधित था और जिसकी विषय पंक्ति थी, बांग्लादेशी भाषा में लिखे गए

दस्तावेज़ों का अनुवाद। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर एक कथित पत्र में बंगाली को 'बांग्लादेशी राष्ट्रीय भाषा' करार दिये जाने पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह 'अपमानजनक, राष्ट्र-विरोधी और असंवैधानिक' है। ममता बनर्जी ने पत्र की एक प्रति साझा करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, ''देखिए, अब कैसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में दिल्ली पुलिस बांग्ला को 'बांग्लादेशी' बता रही है।'' ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्ला न केवल उनकी मातृहै, बल्कि रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की भी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्ला ही वह है जिसमें भारत का राष्ट्रगान (टैगोर द्वारा रचित 'जन गण मन') और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम', दोनों लिखे गए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि वह जिसमें करोड़ों भारतीय बोलते और लिखते हैं, वह जिसे भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे अब बांग्लादेशी बताया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराया और कहा कि पश्चिम बंगाल में बोली और लिखी जाने वाली बांग्ला और बांग्लादेश की बोली में अंतर है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का बचाव करने की कोशिश कर रही है जो उर्दू से प्रभावित बांग्ला बोलते हैं।

झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन

नई दिल्ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शिबू सोरेन ने झारखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी अंतिम सांस सुबह 8:48 बजे ली गई। उनके निधन की खबर से झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत और झारखंड के गठन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कमी झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नुकसान है। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता और संस्थापक संरक्षक थे, जो पिछले 38 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को बिहार के हजारीबाग जिले में हुआ था, जो अब झारखंड का हिस्सा है। जनता में उन्हें 'दिशोम गुरु' और 'गुरुजी' के नाम से सम्मानित किया जाता था। शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष से की और 1970 के दशक में धनकटनी आंदोलन समेत कई आंदोलनों के जरिए आदिवासी समाज की आवाज को मजबूती से उठाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर सोमवार शाम करीब 5.30 बजे दिल्ली से रांची लाया गया, झामुमो के एक नेता ने बताया। उन्होंने कहा, मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ जिले में उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम के निधन के बाद झारखंड में तीन दिनों का राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड में विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया

पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, शिबू सोरेन जी एक ज़मीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की। शांति.

शिबू सोरेन के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक, झारखंड में आज दोपहर तीन बजे मुखाग्नि दी जाएगी

झारखंड और भारतीय राजनीति को गहरी क्षति- राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- शिबू सोरेन जी के निधन से झारखंड और भारतीय राजनीति की गहरी क्षति हुई। उनके आदिवासी कल्याण और झारखंड गठन के योगदान अविस्मरणीय हैं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ।

शिबू सोरेन के निधन पर राहुल गांधी ने क्या कहा

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ. आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़, सोरेन जी ने उनके हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया. झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा. हेमंत सोरेन जी और पूरे सोरेन परिवार के साथ-साथ गुरुजी के सभी समर्थकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

बहुत दुखद खबर- प्रियंका गांधी वाड्रा

झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के निधन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैंने कल्पना जी (कल्पना सोरेन) को मैसेज किया है। यह हम सभी के लिए बहुत दुखद खबर है। हम परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ है।